Publication	Herald Youngleader	Date	16-07-2018	Page No.	11
Medium	Print	Edition	Ahmedabad		

कृषि क्षेत्र को मानकीकृत बनाने का तरीका है खाद्य सुरक्षा

श्री संदीप सभरवाल, सीईओ, एसएलसीएम ग्रुप –सतत् आर्थिक वृद्धि के लिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। कृषि क्षेत्र के मानकीकरण में इसकी भूमिका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगकारक है। भारत जैसे देश के लिए यह खास तौर पर सत्य है जहां सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र की प्रगति में यह निरंतर ठोस भूमिका निभाती आई है, बावजूद इसके कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसके योगदान में गिरावट आई है। वर्तमान में देश में कुल जितने भी लोग रोजगार पर लगे हैं उनमें से लगभग दो तिहाई को कृषि क्षेत्र में ही रोजगार मिला हुआ है जो भारत के जीडीपी में 18 प्रतिशत (वर्ष 2014 का आंकड़ा) योगदान कर रहे हैं। हमारे देश ने अन्न उत्पादन में आत्म निर्भरता हासिल कर ली है। पर फिर भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी कृषि क्षेत्र के पास है किंतु यह क्षेत्र कम पैदावार और खाद्य की बर्बादी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्याएं मुख्य रूप से वित्तीय, प्रबंधन और तकनीकी सीमाओं से संबंधित हैं जो कि फसल कटाई की तकनीक, भंडारण और कूलिंग सुविधाओं के मामले में पेश आती हैं जिनका रिश्ता मुश्किल मौसमी स्थितियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग और मार्केटिंग प्रणालियों से है। इसलिए ऐसी रणनीतियां और नीतिगत प्रतिक्रियाएं अपनाने की आवश्यकता है जो कृषि क्षेत्र को अप्रत्याशित घटनाओं से बचा सकें, निरंतर बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए उपज बढ़ाएं तथा खाद्य बर्बादी की समस्या का निवारण करें – खाद्य पदार्थों का सही भंडारण एवं वितरण एक गंभीर चुनौती है। अन्य विकल्पों में शामिल हो सकते हैं– कृषि क्षेत्र को संस्थागत सहयोग प्रदान करना जिसके लिए इन्हें जरिया बनाया जा सकता है– खाद्य व्यापार, फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, जल आवंटन, भूमि उपयोग पैटर्न और खाद्य कीमतें व सुरक्षा सुनिश्चित करना।